गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) :(क) स्वीकृत किये ऋण निम्न प्रकार थे :-

1968-69	रु. 6,27,06,700
1969-70	रु. 5,08,58,500
1970.71	रु. 6,67,75,000

(ख) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान स्वीकृत किये गये ऋणों पर कुल 92,54,276 रुपये का ब्याज बना । वर्ष 1970-71 के दौरान स्वीकृत किये गये ऋण पर अभी तक कोई ब्याज देय नहीं हुआ है ।

(ग) रु. 7,37, 72,000

(घ) 5½ प्रतिशत प्रतिवर्ष, जिसमें मूलधन तथा ब्याज की समय पर अदायगी करने के लिए ¼ प्रतिशत छूट हैं ।

National Plan for Geo-Dynamics Projects

1629. SHRI SAMINATHAN : Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) the salient features of national plan for geo-dynamics Projects discussed at the recent two-day conference of Scientists held in New Delhi during April, 1971 ; and

(b) the areas chosen for studying the movements taking place in the interior of the earth ?

THE MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF DEPARMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM) : (a) and (b). The Indian National Committee for Co-operation with the International Union of Geodesy and Geophysics held a panel discussion on the 2nd and 3rd April, 1971 to consider India's participation in an international Geodynamics project which is being organised to study the solid earth. The following working Groups were set up to deal with different aspects of the project.

Subject	*Coordinator*
(i) Seismology	Dr. A.N. Tandon
(ii) Laboratory studies on Physical properties	Dr. S. Balakrishna
(iii) Palaeomagnetism	Dr. R.K. Verma
(iv) Patrology, Minerology and Geochronology	Dr. A. P. Subramaniam
(v) Surveys	Shri J. Chatterjee

उत्तर प्रदेश में पौड़ी गढ़वाल जिले का विकास

1630. श्री प्रताप सिंह नेगी : क्या योजना मंत्री गढ़वाल जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने और वहां मद्य निषेध लागू करने के बारे में 14 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6255 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य के पहाड़ी जिलों में सर्वाधिक पिछड़े पौड़ी गढ़वाल जिले के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्न प्रकार है :-

(1) पौड़ी गढ़वाल जिला उन 8 पहाड़ी जिलों में से एक है जिन्हें त्वरित विकास के लिए अपेक्षाकृत पिछड़ा घोषित किया गया है ।

इन पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना अवधि के दौरन राज्य की पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत समग्र केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता एक उदार सिद्धान्त के आधार पर दी जा रहीं है 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 50 प्रतिशत ऋण के रूप में जब कि सामान्य सिद्धान्त के अनुसार 30 प्रतिशत सहायता अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है। साथ ही प्रत्येक वर्ष की वार्षिक योजना के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्र की योजना के लिए व्यय व्यवस्था की गई है अतः इसका व्यपवर्तन नहीं किया जायेगा।

राज्य की चौथी योजना में पहाड़ी क्षेत्र के लिए 65.05 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जिसमें 6.94 करोड़ रुपये पौड़ी गढ़वाल जिले के के लिए है। इस परिव्यय का विकास की मूख्य मदों के अनुसार ब्योरा तथा चौथी योजना के प्रथम दो वर्ष 1969—71 के व्यय की प्रगति यहां नीचे दर्शायी गई है :-

पौड़ी गढ़वाल का परिव्यय तथा व्यय

(लाख रुपयों में)

विकास की मूख्य मद	चौथी योजना का परिव्यय	1969-70 का व्यय	1970-71 का प्राक्कलित व्यय
1. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रम	254.340	27.350	32.432
2. सहकारिता तथा सामुदायिक विकास	24.810	6.283	5.126
3. सिंचाई तथा बिजली	66.710	16.020	50.680
4. उद्योग तथा खनन	17.790	1.421	1.500
5. परिवहन तथा संचार	178.040	33.296	50.954
6. समाज सेवाएं	151.970	38.910	27.110
7. विविध	0.480	0.018	0.064
जोड़ :	694.140	123.298	167.866

(2) इस जिले को उन केन्द्र प्रयोजित स्कीमों से भी लाभ होगा जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिय कार्यान्वित की जा रही हैं :

(3) वित्तीय तथा ऋणदात्री संस्थाओं से लघु मध्यम तथा छोटे उद्योगों के लिए रियायती वित्त प्राप्त करने हेतु पौड़ी गढ़वाल जिले का वर्गन एक पिछड़े जिले के रूप में किया गया है।

(4) राज्य सरकार को ज्ञात है कि वह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा विकास एवं अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं जुटाने के लिए पौड़ी गढ़वाल के लिए एक जिला योजना तैयार करे। इस हेतु एक निर्देश समिति के तत्वावधान में एक सघन सर्वेक्षण की बात पर विचार किया जा रहा है। इस समिति के अध्यक्ष योजना आयोग के एक सदस्य है तथा राज्य योजना एवं वित्त सचिव और राज्य कृषि आयुक्त, योजना आयोग के सलाहकार (उद्योग तथा खनिज) तथा सम्बन्धित सलाहकार (कार्यक्रम प्रशान) सदस्य हैं।

(5) इस जिले को ग्राम बेरोजगारी के तूफ़ानी कार्यक्रम से भी लाभ होगा जिसे सारे देश में 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की व्यवस्था करके चलाया गया है।

(6) हाल ही में एक ग्राम बिजली करण निगम की स्थापना की गई है। यह निगम पौड़ी गढ़वाल जिले जैसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में ग्राम बिजली करण कार्यक्रमों के लिए राज्य बिजली बोर्डों को रियायती शर्तों पर धन दे रहा है।

Exports of Cashewnuts

1631. SHRI K; LAKKAPPA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to stote :

(a) the progress made by Government to boost the export of Cashewnuts ;

(b) the, foreign exchange earned as a result of the export of Cashewnuts during the last three years, year-wise; and

(c) what are Government's plan to increase the export of Cashewnuts ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) and (c). For export of Cashew Kernels, we are mostly dependent on imported nuts. As a long term measure, therefore, the Ministry Food and Agriculture is taking steps to increase indigenous production. Simultaneously, we are trying to explore new markets for which various promotional measures, such as participation in Trade Fairs, sending out delegations and arranging special promotional measures, are being undertaken. The State Trading Corportion has also been asked to promote the exports of Cashew Kernels, specially to non-traditional markets,

(b) Exyorts of cashewnuts during 1968-69, 1969-70 and 1970-71 were of the order of Rs. 60.92 crores, Rs. 57.42 crores and Rs. 52.03 crores respectively bringing the net foreign exchange earning to Rs. 29.54 crores during 1968-69, Rs. 29.82 crores during 1969-70 and Rs. 22 78 crores during 1970-71.

नैनीताल में लगाये जाने वाले उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर का अन्य स्थान पर लगाया जाना

1632. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि :

(क) क्या उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर को जिसे पहले नैनीताल के निकट लगाया जाना था अब किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस स्थान का क्या नाम है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). यह ट्रांसमीटर अब नजीबाबाद में लगाया जायेगा। तथापि, दो स्टूडियो अल्मोड़ा और पौड़ी में लगाए जायेंगे। ट्रांसमीटर लगाने के लिए नजीबाबाद का चयन कुमायूं गढ़वाल प्रदेश के अधिक से अधिक क्षेत्र में प्रभावी ढंग से प्रसारण